

एकांगी दृष्टिकोण के असर में मानवाधिकार संगठन



उमेश चतुर्वेदी

बीस जुलाई के संसद मार्च के पहले तक नीट और दूसरी परीक्षाओं में धांधली रोकने की मांग वाला आंदोलन मर्यादित दायरे में था। हालांकि इस दौरान भी शांत खड़े सुरक्षा बलों के साथ बदसलूकी हुई, प्रधानमंत्री को गंदी-गंदी गालियां देते हुए पोस्टर सार्वजनिक रूप से लहराये गए। इन्हें सोशल मीडिया पर उतेजित अंदाज में प्रस्तुत भी किया गया।

यह कोई पहला मौका नहीं है, जब भारतीय सुरक्षा बलों और सरकार पर उसकी कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठया हो। कश्मीर घाटी में आतंकी मासूम खून बहाते रहे, तब मानवाधिकार संगठनों ने कोई सवाल नहीं उठया, लेकिन जब भी इन आतंकियों के खिलाफ भारतीय बलों ने कड़ी कार्रवाई की, उनके समर्थकों को सीखचों के पीछे डालना शुरू किया, मानवाधिकार संगठनों को उनके मानवाधिकार की चिंता होने लगी। ऐसे में हालिया आंदोलनों के दौरान भारत सरकार की कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार संगठन सवाल नहीं उठाते तो ही हैरत होती। नीट परीक्षा के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के बीस जुलाई के संसद मार्च के दौरान जो हिंसा हुई, उसके खिलाफ अगर सुरक्षा बल, ताकत का इस्तेमाल नहीं करते तो बाद में वे ही सवालों के घेरे में होते। संसद से महज दो सौ मीटर की दूरी पर जिस तरह आंदोलन में शामिल असामाजिक और अराजक तत्व उकसाऊ कार्रवाई कर रहे थे, उसमें पुलिस और प्रशासन के पास बल प्रयोग के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। दुनिया की उदार से उदार समझी जाने वाली शायद ही कोई सरकार होती, जो अपनी संसद में उपद्रवियों को घुसने की राह देती। सोचिए अगर, उस दिन उपद्रवी संसद में घुस जाते और भारतीय संसद के साथ कुछ वैसी ही अनहोनी होती, जैसा अभी हालिया प्रदर्शन के दौरान अल्बानिया में हुआ है तो क्या भारतीय लोकतांत्रिक समाज उसे स्वीकार कर पाता? निश्चित तौर पर इन सवालों का जवाब सिर्फ ना है। भारत में हालिया आंदोलनों की शुरुआत नीट परीक्षा में धांधली के विरोध में हुई। इसी दौरान अचानक से एक नई पार्टी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ बनी और उसके बैनर तले देशभर के युवाओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर डेरा डाल दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलनों को शांति आंदोलनों के रूप में देखा जाता है। मर्यादित आंदोलनों और धरना-प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक समाज अपने गुस्से का इजहार करता रहा है। समझदार सरकारें भी सीमित और मर्यादित आंदोलनों को लोगों के गुस्से की अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में लेती रही हैं। मर्यादित आंदोलनों के जरिए लोक अपना गुस्सा निकालकर शांत हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि



लोक में अराजक तत्व भी होते हैं और वे आंदोलनों की ताक में रहते हैं। लोकतांत्रिक आंदोलनों में वे मौका पाते ही घुस जाते हैं और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बीस जुलाई के संसद में मार्च में ऐसा ही हुआ। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने में जेनुइन छात्रों की संख्या कम, अराजक और असामाजिक तत्वों की संख्या ज्यादा रही। इस तथ्य को सुरक्षा बलों ने भी स्वीकार किया है। बीस जुलाई के संसद मार्च के पहले तक नीट और दूसरी परीक्षाओं में धांधली रोकने की मांग वाला आंदोलन मर्यादित दायरे में था। हालांकि इस दौरान भी शांत खड़े सुरक्षा बलों के साथ बदसलूकी हुई, प्रधानमंत्री को गंदी-गंदी गालियां देते हुए पोस्टर सार्वजनिक रूप से लहराये गए। इन्हें सोशल मीडिया पर उतेजित अंदाज में प्रस्तुत भी किया गया। फिर भी सरकारी तंत्र संयमित रहा। सुरक्षा बलों के सरम रूख के पीछे आंदोलन में शामिल युवा रहे। सुरक्षा बलों और प्रशासन को लगता था कि अगर युवाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन जैसे ही यह आंदोलन एसआईआर के

खिलाफ और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और बढ़ा, इसने राजनीतिक रंग ले लिया। निश्चित तौर पर इस पूरे आंदोलन में छात्र कहीं नेपथ्य में जाते हुए दिखे और मोर्चे पर कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दल दिखे। लेकिन सुरक्षा बलों ने अपना संयम बनाए रखा। चुनाव आयोग पर प्रदर्शन के लिए संसद से निकले विपक्षी सांसदों और उनके समर्थकों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। लोगों को जुटने से रोका गया। हो सकता है कि इस दौरान कुछ लोगों के साथ हाथापाई भी हुई हो, किसी को चोट लगी हो। आंदोलन में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। दुनिया की कोई भी सरकार आंदोलनकारियों का फूलों से स्वागत नहीं करती। सरकार और सुरक्षा बलों ने जिस तरह संयम दिखाकर सिर्फ हिरासत में लेकर आंदोलन को हिसक होने से रोकने में सफलता पाई, उसका समाज के एक बड़े हिस्से ने स्वागत भी किया है। आंदोलनकारियों के खिलाफ सदकों पर उतरी जनता को आसानी से भाजपा का एजेंट कहा जा सकता है। लेकिन त्योहारी मौसम में कारोबारी नुकसान पहुंचा रहे कर्नाट प्लेस

के कारोबारियों का आंदोलन के विरोध में खड़ा होना मामूली बात नहीं है। इससे साफ हुआ कि जनता भी ऐसे आंदोलनों को पसंद नहीं कर रही। दुर्भाग्य यह है कि चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या फिर ह्यूमनराइट्स वाच, या संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम, सुरक्षा बलों के संयम, प्रधानमंत्री को दी गई गालियों की ओर ध्यान नहीं दिया। एसआईआर और नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ हुए आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति एवं विशेषज्ञों का चिंता जताना दरअसल मामले का एक तरफा सज्जान लेना है। ह्यूमन राइट्स वॉच और संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति यानी यूएनसीईआरडी ने अपनी रिपोर्टों में, देश में धार्मिक अल्पसंख्यकोंके खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाने और उनके खिलाफ नफरती भाषण आदि का आरोप लगाया है। ये संगठन विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम यानी एफसीआरए और कड़े आतंकवाद-विरोधी कानूनों, मसलन यूएपीए के दुरुपयोग का भी भारत पर आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि इन नियमों-कानूनों के जरिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, एनजीओ और आलोचकों की आवाज दबाई जा रही है। साथ ही, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा सिकुड़ रहा है। मानवाधिकार संगठन चाहे जो भी कहें, लेकिन विशेषकर राजधानी दिल्ली में जिस तरह सुरक्षा बलों ने खुद पर हुए हमलों के बावजूद जवाबी कार्रवाई में संयम दिखाया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। दरअसल श्रेष्ठताबोध से ग्रस्त पश्चिमी समाज और उसके कथित मानवाधिकार संगठनों का नजरिया विशेषकर तीसरी दुनिया के देशों के लिए एकराका ही रहा है। बेशक भारत आर्थिक रूप से दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति बन चुका है, लेकिन अब भी भारत को लेकर उनकी सोच पुरानी ही है। जिसे अब देश की अधिसंख्य जनता समझने लगी है, इसीलिए अब ऐसे आरोपों और पर्यवेक्षणों से भारतीय मानस उस तरह प्रभावित नहीं होता, जैसा अतीत में होता रहा है।

सम्पादकीय

यूएस और इजराइल के चुनावों से तय होगी युद्ध की तस्वीर

अमेरिका और इजराइल कथित तौर पर नवंबर की शुरुआत में ईरान पर नए सिरों से हमले की योजना बना रहे हैं। अब तक ईरानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने और नौसैनिक नाकेबंदी के जरिए दबाव बनाने के बावजूद अमेरिका ईरान से अपनी मांगें नहीं मनवा पाया है। अभी यह भी



संपादक अनिल खुराना

स्पष्ट नहीं है कि नए हमलों से क्या हासिल हो पाएगा। इससे मध्य-पूर्व में व्यापक तबाही जरूर हो सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हमले पर चर्चा के लिए हाल ही में बेजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। इस बीच, अमेरिका ने हमले के लिए बड़ी सेना भी जुटा ली है। लेकिन हमले के लिए ट्रंप की मंजूरी जरूरी होगी और वे असमंजस में हैं। नए हमले ईरान के ऊर्जा ढांचों, परमाणु ठिकानों के साथ उसके ड्रोन और मिसाइल भंडारों पर हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल को उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर एक और हमला ईरान को आखिरकार उनकी मांगें मानने को मजबूर कर देगा, खासकर परमाणु कार्यक्रम के मामले पर। इधर ईरान भी साफ कर चुका है कि वह मध्य-पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को और आक्रामक तरीके से निशाना बनाएगा, अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने की कोशिश करेगा और सऊदी अरब जैसे देशों के ऊर्जा ढांचे, हवाई अड्डों और तेल पाइपलाइनों पर हमले करेगा, जिससे तेल कीमतें उछल सकती हैं। वास्तव में, ईरान ने अपने हालिया मिसाइल हमलों में पहले की तुलना में अधिक क्षमता प्रदर्शित की है। इनमें जुलाई में जॉर्डन स्थित मुवफ्फक सलती एयरबेस पर किया गया हमला शामिल है। सितंबर के हमलों में तो ईरानी मिसाइलें अमेरिकी युद्धपोतों के काफी करीब पहुंच गई थीं। विश्वेकोष में कहा है ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और उसने इनका उत्पादन फिर शुरू कर दिया है।अमेरिका अब मान रहा है कि ईरानी हमलों ने उसके एयरबेस, दूतावासों और बहरीन स्थित पांचवें बड़े के मुख्यालय को काफी नुकसान पहुंचाया है। हमलों में यूएई और कतर के ऊर्जा एवं औद्योगिक ठिकानों तथा दुबई, कुवैत, बहरीन के हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया। अब ईरान का लक्ष्य पड़ोसी देशों को और नुकसान पहुंचाना होगा। पिछले हफ्ते इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक कमांडर ने कहा कि ईरान होमुज के नीचे से गुजरने वाली इंटरनेट केबलों को काट सकता है। इससे ज्यादातर खाड़ी देशों में कनेक्टिविटी ब्लैकआउट हो सकता है, हालांकि कुछ देशों के पास जमीनी रास्तों के जरिए वैकल्पिक नेटवर्क भी हैं। सऊदी अरब और यूएई में अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के क्लाउड तथा एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो सकते हैं। वित्तीय और बैंकिंग लेन-देन धीमे हो सकते हैं। भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि बैंडविड्थ का एक बड़ा हिस्सा ग्लोब-मुम्बई कॉरिडोर से होकर ही गुजरता है। कुछ ही दिनों पहले ईरान की संसद ने देश के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख योजनाकार मेहरदाद अखलाघी को रक्षा मंत्री नियुक्त किया। पद संभालते ही अखलाघी ने कहा कि उनका फोकस नई तकनीकों पर रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मीडिया में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि हानए हमले नागरिकों के जीवन, क्षेत्र के सभी देशों की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को जोखिम में डाल देंगे। राजनीतिक रूप से देखें तो ये हमले उन परिस्थितियों में होने वाले हैं, जो तेजी से बदल सकती हैं। इजराइल के चुनावों में बेजामिन नेतन्याहू की हार भी संभव है और अमेरिका में 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों में ट्रंप को कोई बड़ा नुकसान हुआ तो सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हमलों का एक और दौर वह नतीजा हासिल कर सकता है, जो महीनों के सैन्य दबाव के बावजूद हासिल नहीं हो पाया? नतीजे में किसी राजनीतिक समझौते के बगैर हुए युद्ध की कीमत बहुत बड़ी होगी।



मनोज कुमार अग्रवाल

इन दिनों फ्रांस में चल रहा आंदोलन हालांकि मूल रूप से महंगाई और खराब सार्वजनिक सेवाओं के खिलाफ उपजा जन-आक्रोश से शुरू हुआ , जिसे उग्र वामपंथी तत्वों, सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार फैलाने वाली विदेशी ताकतों और आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपने-अपने एजेंडे के लिए भुनाना शुरू कर दिया है।यह भी सामने आया है कि इन देशों में आसान आब्रजन नियमों का फायदा उठा घुस आए प्रवासी अराजकता का नंगा नाच कर रहे हैं। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों इटली, स्पेन, बेल्जियम और अल्बानिया में भड़की व्यापक हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के पीछे यद्यपि किसी एक निश्चित वैश्विक साजिश के पुष्टा सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इसमें सामाजिक-आर्थिक कारण, स्थानीय जनक्रोश का कई



सौरभ वाष्या

तो चोरी के आरोपों से शुरू हुआ आंदोलन, सरकार की जवाबदेही, विपक्ष की भूमिका और युवाओं की बेचैनी के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने कई सवाल खड़े कर रहा है। देश में चुनावी पारदर्शिता और कथित 'वोट चोरी को लेकर शुरू हुआ आंदोलन धमने का नाम नहीं ले रहा है। दो अक्टूबर से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। जंतर-मंतर जैसे निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शन से संबंधित प्रतिबंधों और प्रशासनिक सीमाओं के बीच आंदोलन की आवाज सड़कों तक सुनाई दे रही है। विपक्षी दलों के साथ युवाओं की भागीदारी और स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने वाले यूट्यूबर्स तथा डिजिटल पत्रकारों की सक्रियता ने इस मुद्दे को एक नया आयाम दिया है। सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन को केवल राजनीतिक विरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर इसके पीछे लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास से जुड़ी चिंताओं को भी समझने की आवश्यकता है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां चुनाव केवल सरकार बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की इच्छा व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर हैं। मतदाता अपने मत के जरिए सत्ता को स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदलने का अधिकार भी रखता है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर उठने वाले सवालों को गंभीरता से सुनना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। हालांकि, 'वोट चोरी' जैसे गंभीर आरोपों को प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर परखा जाना भी उतना ही आवश्यक है। आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना दो अलग-अलग

बातें हैं। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि न तो सवाल पूछने वालों को बिना सुने खारिज किया जाए और न ही बिना प्रमाण किसी आरोप को अंतिम सत्य मान लिया जाए। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के सामने विरोध प्रदर्शनों से निपटने की चुनौती रहती है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का दायित्व है, लेकिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान भी जरूरी है। यदि किसी स्थान पर सुरक्षा, यातायात या कानून-व्यवस्था से संबंधित प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उनके पीछे स्पष्ट कारण होने चाहिए और उनका पालन निष्पक्ष तरीके से कराया जाना चाहिए। सरकार की आलोचना करने वाले प्रत्येक व्यक्त को व्यवस्था विरोधी मान लेना उचित नहीं है। उसी प्रकार आंदोलन के नाम पर कानून तोड़ने या आम नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र में सरकार और प्रदर्शनकारियों, दोनों से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है। यदि आंदोलन को लेकर यह धारणा बनती है कि सरकार असहमति की आवाज को जनता तक पहुंचने से रोकना चाहती है, तो इससे राजनीतिक अविश्वास बढ़ सकता है। दूसरी ओर, यदि आंदोलनकारी तथ्यों के बजाय केवल भावनाओं के आधार पर दावे करते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। बेहतर रास्ता यही है कि चुनावी शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो, संबंधित संस्थाएं तथ्यों के साथ जवाब दें और जनता के सामने स्थिति स्पष्ट की जाए। विपक्ष का काम केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना और जनता के सामने वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना भी है। यदि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाता है, तो उसे ठोस साक्ष्य, व्यवस्थित शिकायतें और तथ्यात्मक तर्क सामने रखने चाहिए। केवल नारों और राजनीतिक आरोपों से जनता का विश्वास लंबे समय तक कायम नहीं रखा जा सकता। साथ ही, सरकार को भी यह समझना होगा कि विपक्ष की हर आलोचना को राजनीतिक षड्यंत्र बताकर खारिज कर देना समस्या का समाधान नहीं है। लोकतंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी अवश्य

हैं, लेकिन दोनों की जवाबदेही अंततः जनता के प्रति है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता भी इसी में है कि उसके निर्णयों, प्रक्रियाओं और शिकायत निवारण व्यवस्था पर जनता का भरोसा बना रहे। इस आंदोलन के बीच यूट्यूबर्स और स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारों की भूमिका विशेष रूप से ध्यान खींचती है। पहले समाचारों और राजनीतिक विमर्श पर मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव था, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया ने आम नागरिकों को भी अपनी बात व्यापक स्तर पर रखने का अवसर दिया है। आज कोई युवा घटनास्थल से वीडियो साझा कर सकता है, किसी सरकारी दावे की पड़ताल कर सकता है और उन मुद्दों को सामने ला सकता है जिन्हें पर्याप्त जगह नहीं मिल रही हो। यह बदलाव लोकतंत्र के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछने और जनता की समस्याओं को सामने लाने में उपयोगी हो सकती है। लेकिन हर यूट्यूबर स्वतंत्र पत्रकार नहीं बन जाता। विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए तथ्यों की पुष्टि, दोनों पक्षों को सुनना, स्रोतों की जांच करना और गलत सूचना फैलाने से बचना अनिवार्य है। वायरल होना और विश्वसनीय होना अलग-अलग बातें हैं। इसलिए डिजिटल माध्यमों से उठने वाली आवाजों को केवल उनकी राजनीतिक पसंद के आधार पर खारिज करना उचित नहीं है। उनकी सामग्री की जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। स्वतंत्र पत्रकारिता का वास्तविक महत्व तभी है, जब वह सत्ता से भी सवाल पूछे और विश्व के दावों की भी निष्पक्ष पड़ताल करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं के सामने विकास, रोजगार, अवसरों और बेहतर भविष्य की उम्मीदें रखी थीं। आज युवाओं का एक वर्ग रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, महंगाई, शिक्षा और राजनीतिक जवाबदेही जैसे सवालों को लेकर मुछर दिखाई देता है। ऐसे में किसी भी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को केवल राजनीतिक दलों के प्रभाव का परिणाम मान लेना अधूरा विश्लेषण होगा। युवाओं की अपेक्षाएं बदल रही हैं। वे केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि उनके परिणाम भी देखना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि रोजगार के अवसर कितने बड़े, शिक्षा कितनी सुलभ हुई, सरकारी संस्थाओं में

पारदर्शिता कितनी मजबूत हुई और उनकी समस्याओं पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई की गई। यह जरूरी नहीं कि आंदोलन में शामिल प्रत्येक युवा किसी एक राजनीतिक विचारधारा का समर्थक हो। कई बार असंतोच का कारण किसी दल के प्रति समर्थन या विरोध से अधिक अपने भविष्य को लेकर चिंता होती है। सरकार के लिए यह अवसर है कि वह युवाओं की शिकायतों को सुने, उपलब्धियों के साथ कमियां पर भी स्पष्टता से बात करे और ठोस नीतिगत समाधान सामने रखे। लोकतांत्रिक सरकार की ताकत केवल चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि आलोचना सुनने और जनता के भरोसे को बनाए रखने में भी होती है। वोट चोरी के आरोपों से जुड़े आंदोलन का वास्तविक निष्कर्ष नारों, रैलियों या राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि तथ्यों, जांच और संस्थागत पारदर्शिता के निकलेगा। यदि आरोपों में दम है, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आरोप प्रामाणित नहीं होते, तो संबंधित संस्थाओं को स्पष्ट और विश्वसनीय तथ्यों के माध्यम से स्थिति सामने रखनी चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में जनता को भरोसेमंद जवाब मिलना जरूरी है। जंतर-मंतर पर प्रतिबंध हो या सड़कों पर विरोध, लोकतंत्र की असली परीक्षा इस बात में है कि असहमति के लिए कितनी जगह बची है और सवालों के जवाब कितनी ईमानदारी से दिए जाते हैं। सरकार को कानून-व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना होगा। विपक्ष को भी अपने आरोपों को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करना होगा। वहीं विपक्ष पत्रकारों और आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी है कि वे सत्यापन, शांति और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करें। आखिरकार, लोकतंत्र केवल बहुमत से सरकार बनाने का नाम नहीं है। वह जनता के विश्वास, संस्थाओं की निष्पक्षता और नागरिकों के सवाल पूछने के अधिकार से भी मजबूत होता है। यदि सरकार, विपक्ष और संवैधानिक संस्थाएं इस मूल भावना को समझें, तो आंदोलन टकराव का कारण बनने के बजाय व्यवस्था में सुधार का अवसर बन सकता है। जनता को न केवल अपने मताधिकार की सुरक्षा का भरोसा चाहिए, बल्कि यह विश्वास भी चाहिए कि उसकी आवाज सत्ता तक पहुंच सकती है और उसके सवालों का जवाब मिलेगा। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है।

यह (एक् यूरेट मिरर) साप्ताहिक समाचार पत्र (प्रकाशक अनिल खुराना) द्वारा (प्रकाशन स्थल ए/3, इम्पूरवोमेंट ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स, पटेल चौक, पठानकोट, पंजाब 145001) से (स्वामी अनिल खुराना) की ओर से प्रकाशित की जाती है। (संपादक अनिल खुराना) द्वारा (मुद्रक योगेश कुमार) द्वारा (प्रिंटिंग प्रेस – विशाल दर्पण, 50/51, नारी शिल्प मंदिर मार्ग, चकराता रोड, देहरादून, उत्तराखंड) से मुद्रित की जाती है। दूरभाष नंबर: +91 9814198141 RNI.PRGI NO. PBHIN/25/A3708, Email: anil@aminews.co.in / anilk8877@gmail.com website- www.aminews.co.in (नोट: यह साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है, प्रकाशित सामग्री के सम्बन्ध किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पठानकोट, पंजाब न्यायालय ही मान्य होगा।)



पुल बचा, रास्ते बह गए... क्या अब पुल के गिरने का इंतज़ार कर रहा है प्रशासन ?

एक्यूरेट मिरर

हिमाचल प्रदेश की इंदौरा तहसील के मंड भोगरवां क्षेत्र में साल 2025 की भीषण बाढ़ की तबाही के निशान आज भी साफ दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ के प्रचंड प्रवाह में मंड भोगरवां का पुल तो जैसे-तैसे खड़ा रह गया, लेकिन इसे दोनों तरफ से जोड़ने वाले एप्रोच मार्ग पूरी तरह बह गए। कभी लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने वाला यह पुल आज खुद रास्ते से कटकर बीच नदी में एक अलग-थलग ढाँचे की तरह खड़ा है। बाढ़ के दौरान इस इलाके के ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें घर, उपजाऊ खेत, फसलें और पशुधन तबाही की भेंट चढ़ गए थे।

स्थानीय लोगों का गंभीर आरोप है कि क्षेत्र में क़रार संचालकों द्वारा किए गए बेतहाशा और अवैध खनन ने बाढ़ के प्रकोप तथा तबाही के मंजर को और अधिक भयावह बना

धर्मशाला/कांगड़ा से सीधे जुड़ेगे देश के बड़े शहर: गगमल एयरपोर्ट पर मांझी खडु पर बनेगा 380 मीटर लंबा पुल

एक्यूरेट मिरर

हिमाचल प्रदेश के सबसे व्यस्त गगमल एयरपोर्ट (कांगड़ा एयरपोर्ट) के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। विस्तार परियोजना की टेक्नो इकोनॉमिक फ़िजिबिलिटी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद अधिकृत एजेंसी वेपकोस इस रिपोर्ट को तैयार करने में जुटी है। एजेंसी द्वारा रिपोर्ट विभाग को सौंपने के बाद इसे राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्ययोजना तय होगी। परियोजना के तहत रनवे की लंबाई को मौजूदा 1,376 मीटर से बढ़ाकर 3,010 मीटर करने की योजना है। इससे ए-320 जैसे बड़े यात्री विमानों के संचालन का रास्ता खुलेगा और दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से

कुलदीप सिंह पटानिया ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात

चुवाड़ी-चम्बा सुरंग और ज़ोत-साच-पांगी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की उठाई मांग



एक्यूरेट मिरर

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानिया ने नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सरकारी आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट की। इस विशेष मुलाकात के दौरान विश्वासभाषा अध्यक्ष ने जिला चम्बा की विभिन्न महत्वपूर्ण और लंबित सड़क परियोजनाओं तथा बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान कुलदीप सिंह पटानिया ने चम्बा जिले में आवागमन को सुगम बनाने और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के कायाकल्प पर



दिया था। हालाँकि, इस तबाही के बाद भी ज़मीनी हकीकत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। उसी कटे हुए पुल के ठीक आसपास आज भी बेफ़िक्र होकर भारी मशीनें और टिप्पर चलाए जा रहे हैं। दिन के उजाले में खुलेआम नदी के तल से खनिज संपदा निकाली जा रही है और मशीनों की बकेट से उठाकर टिप्परों में सामग्री भरी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस पुल के पहुँच मार्ग तक

बह चुके हैं, उसके इतने नजदीक हो रही खुदाई की गिरानी आखिर कौन सा विभाग कर रहा है? माइनिंग विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह खुदाई किस अनुमति के तहत हो रही है, स्वीकृत खनन क्षेत्र की सीमा कहाँ तक है और क्या पुल की सुरक्षा को लेकर संबंधित विभागों ने कोई तकनीकी जाँच रिपोर्ट तैयार की है।

इस स्थिति ने स्थानीय प्रशासन, खनन विभाग और पुलिस की



कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि यह कार्य वैध अनुमति के तहत हो रहा है, तो उसकी शर्तें और सीमांकन सार्वजनिक किया जाना चाहिए और यदि यह अवैध है, तो खुलेआम चल रही इन मशीनों पर अब तक शिकंजा क्यों नहीं कसा गया?

इसके साथ ही क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिनिधियों, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि

उन्होंने इस गंभीर जनसमस्या और अवैध खनन के मुद्दे को किस शतर पर उठाया है। मंड भोगरवां का यह आधा-अधूरा खड़ा पुल सिर्फ़ पिछली आपदा की निशानी भर नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही के बीच आने वाली एक और तबाही की पूर्व चेतावनी है। अब देखना यह होगा कि ज़िम्मेदार विभाग समय रहते कोई ठोस कार्रवाई करते हैं या फिर इस बचे हुए ढाँचे के बह जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश को पर्यटन हब बनाने की तैयारी अगले 5 वर्षों में होगा 15 हजार करोड़ का निवेश

एक्यूरेट मिरर

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के पर्यटन क्षेत्र को एक नई पहचान देने और आर्थिक समृद्धि को गति देने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश की योजना बना रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में हाई-एंड यानी महंगे पर्यटन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करना और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। शिमला जिले के ऐतिहासिक नालदेहरा गोलफ कोर्स में आयोजित दो दिवसीय 'कोटी गोलफ कप-2026' के समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बेहतर



कनेक्टिविटी और आधुनिक बुनियादी ढांचे के दम पर सरकार प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय शतर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। राज्य में एयर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार का लक्ष्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट सुविधाओं से जोड़ना है, ताकि दूर-दराज के इलाकों तक पर्यटकों की पहुंच आसान हो सके। वहीं, शिमला से नियमित कनेक्टिंग उड़ानें शुरू

मंडी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पिकअप गाड़ी से डेढ़ किलो से ज्यादा चरस बरामद, चालक गिरफ्तार

एक्यूरेट मिरर

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सरकावाट थाना क्षेत्र में नकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 1.567 किलोग्राम चरस बरामद की है। तत्क़र ने पुलिस की आंखों में धूल झाँकने के लिए नशे की इस खेप को गाड़ी के अंदर बेहद शांतिराना तरीके से छिपा रखा था, लेकिन पुलिस की नज़ी नजर से वह बच नहीं सका। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन सरकावाट पुलिस की एक टीम चंडेशा इलाके में मौजूद थी और बाहनों की निगरिमा वैक़िग कर रही थी। इसी दौरान पटड़ीघाट की दिशा से आ रही एक पिकअप गाड़ी को जांच के लिए



रोका गया। तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर धातु की एक प्लेट संदिग्ध अवस्था में लगी हुई मिली। जब पुलिस ने उस प्लेट को हटाकर देखा, तो उसके नीचे छिपाकर रखा गया एक पैकेट बरामद हुआ। पैकेट को खोलने पर उसमें से 1 किलो 567 ग्राम चरस पाई गई। पुलिस ने मौके पर ही चरस की खेप को सील कर अपने कब्जे में ले लिया और गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए

मनाली में स्कूली बच्चों को घुमाने लाए हरियाणा के बस चालक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत, परिजनों में छाया मातम

एक्यूरेट मिरर

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू अंतर्गत मनाली से एक दुर्घट समाचार सामने आया है, जहाँ हरियाणा से स्कूली विद्यार्थियों के दल को शैक्षणिक भ्रमण पर लेकर आए एक बस चालक की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण मृत्यु हो गई। इस असमय हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव सहित स्कूल स्टाफ में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक चालक की पहचान हरियाणा के झज्जर जिले के गांव शिवाणा निवासी 32 वर्षीय योगेश पुत्र

रणधीर सिंह के रूप में की गई है। वह दुर्घटन स्थित मॉडल गुरुकुल पब्लिक स्कूल की बस चलाते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार योगेश स्कूल प्रबंधन के साथ 44 विद्यार्थियों, जिनमें 18 छात्र और 26 छात्राएं शामिल हैं, को लेकर मनाली पहुंचे थे। दोपहर लगभग 1:40 बजे जब सभी विद्यार्थी और स्कूल प्रबंधन बशिश मंदिर के दर्शन के लिए पैदल जा रहे थे, तभी रास्ते में चालक योगेश की अचानक तबीयत खराब हो गई और वह चक्कर खाकर सड़क पर गिर पड़े। घटना घटित होते ही मौके पर हड़कंप मच गया और स्कूल प्रबंधन ने

बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हालाँकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम ने मौके पर अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया तथा प्रारंभिक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा परिजनों को सूचित कर दिया गया है और उनके मनाली पहुंचने के पश्चात शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट सुविधाओं से जोड़ने का लक्ष्य

राज्य में एयर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण एा ही लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, उड़ान संचालन को सुगम बनाने रखकों और वित्तीय सहायता देने के लिए 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' तंत्र के तहत 35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट सुविधाओं से जोड़ना है, ताकि दूर-दराज के इलाकों तक पर्यटकों की पहुंच आसान हो सके। वहीं, शिमला से नियमित कनेक्टिंग उड़ानें शुरू करने के प्रयास भी अंतिम चरण में हैं।

करने के प्रयास भी अंतिम चरण में हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार से बड़े विमानों की लैंडिंग संभव हो सकेगी, जिससे पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने की उम्मीद है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्रार्थमिकता देते हुए राज्य सरकार ने इको-टूरिज्म पर भी बड़ा दांव खेला है। प्रदेश में 60 इको-टूरिज्म स्थलों को लीज पर दिया गया है, जो जिससे राज्य के खजाने को 22 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ

है। इसके अलावा, खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नालदेहरा गोलफ कोर्स के सौंदर्यीकरण और विकास पर 1.82 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक गोलफ कोर्स को अब आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और इसे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के निरंतर प्रयास जारी हैं।

हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में मछली उत्पादन बढ़ाने की मुहिम

पोंग झील में 17 लाख मछली के बच्चे छोड़ने का लक्ष्य



एक्क्यूरेट मिरर

हिमाचल प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और मछुआरों की आर्थिक को सुदृढ़ करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पोंग झील में मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए विभाग ने 17 लाख मछली के बच्चे छोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक लगभग 12 लाख 96 हजार बच्चे झील में छोड़े जा चुके हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना और झील से जुड़े करीब 3600 मछुआरा परिवारों की आय को बढ़ाना है। विभाग को पूरी उम्मीद है कि इस पहल से मछुआरों को सीधा लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश के पांच प्रमुख जलाशयों—पोंग डैम, गोविंद सागर, रणजीत सागर, चमेरा और कोल डैम—में उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज का संग्रहण किया जा रहा है।

अकेले पोंग झील में लगभग 17 लाख कुल बीज संग्रहित किए जा रहे हैं। इसमें रोहू (सात लाख पचास हजार), मृगूल (एक लाख), कतला (पाँच लाख) और ग्रास कार्प (तीन लाख पचहत्तर हजार) जैसी विभिन्न प्रजातियों के बीज शामिल हैं। कैपेसिटी और डिमांड के अनुसार ही जलाशयों में बीजों का वार्षिक तरीके से संग्रहण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निदेशालय स्तर पर एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का कड़ाई से पालन करते हुए बीज के परिवहन, गुणवत्ता और वितरण पर पनी नजर रखी जा रही है ताकि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर सके और मछुआरों का भविष्य और अधिक उज्ज्वल हो सके।

शिमला के रोहड़ू में नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने की धमकी का मामला आया सामने

एक्क्यूरेट मिरर

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और शकशोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे डराने-धमकाने का सनसनीखेज मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। पीड़िता की माँ की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गहराई से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना गत 15 अक्टूबर की है। आरोप है कि रोहड़ू स्थित एक नाबालिग परिसर में पवन नामक व्यक्ति ने 17 वर्षीय पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़िता को

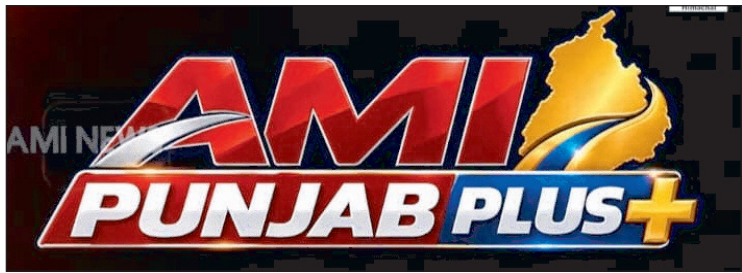


गंभीर परिणाम भुगताने की चेतावनी दी और धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को भी बताया, तो वह उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस गहरे डर और मानसिक प्रताड़ना के चलापों ने लंबे समय तक यह बात अपने परिजनों से छिपाए रखी।

पूरा मामला तब उजागर हुआ जब 23 अक्टूबर को अचानक पीड़िता की तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने

पंजाब चुनाव 2027 को लेकर AMI न्यूज का ऐतिहासिक कदम

नया चैनल 'AMI पंजाब प्लस' लॉन्च, दुनिया भर में गूंजेगी पंजाब की आवाज



एक्स्पूरेट मिरर

आवाज आपकी, सवाल आपके और सरोकार भी आपके- इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए AMI न्यूज ने एक और बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। जब-जब जनता ने अपनी परेशानियाँ और समस्याएँ बताईं, तब-तब AMI न्यूज ने उसे पूरी प्रमुखता के साथ उठाया है और जमीनी हकीकत को देश के सामने बेबाक तरीके से रखा है। जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगकर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार आवाज बुलंद करने के बाद, अब संस्थान अपने दर्शकों के विश्वास के साथ एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 अब बेहद करीब आ चुके हैं और ऐसे में जनता के मन में कई तीखे सवाल तैयार हैं। यह चुनाव इस बात का बड़ा पैमाना होगा

कि नेताओं द्वारा किए गए कितने वादे पूरे हुए और धरातल पर वास्तव में कितना विकास कार्य दिखाई दिया है। इस महत्वपूर्ण दौर में किसने अपनी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया और किसका हिसाब अभी बाकी है, इन तमाम सवालों की पड़ताल करने के लिए AMI न्यूज मैदान में उतर चुका है। इसी उद्देश्य के तहत AMI न्यूज आपके लिए कई नए और विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहा है जिनका मुख्य केंद्र बिंदु पंजाब चुनाव 2027 होगा। इन विशेष कार्यक्रमों के जरिए पंजाब के विभिन्न विधानसभा हलकों से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें जनता की राय, जनप्रतिनिधियों के कामकाज का कच्चा-चिड़ा और नेताओं से सीधे व कड़े सवाल पूछे जाएंगे। चुनाव के दौरान चर्चा सिर्फ राजनीतिक चेहरों की नहीं होगी, बल्कि आपके अपने इलाके के



बुनियादी और वास्तविक मुद्दों की भी जोरदार तरीके से बात होगी। इसी सफर का एक नया और विस्तृत अध्याय जोड़ते हुए AMI न्यूज अपना नया एक्सक्लूसिव चैनल 'AMI पंजाब प्लस' लेकर आ रहा है। पंजाब का चाहे कोई गांव हो या फिर कोई शहर, हर जगह के लोगों की आवाज और उनके स्थानीय मुद्दों को एक और बड़ा और सरासत मंच प्रदान किया जाएगा। दर्शक अब तक हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और AMI न्यूज के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जुड़ते आए हैं, और अब इसी कड़ी में एक नया डिजिटल और टेलीविजन वास्तव होने जा रहा है। इस सप्ताह से शुरू हो रहे 'AMI

पंजाब प्लस' को जियो टीवी, जियो टीवी प्लस, जियो फाइबर, एयर फाइबर, केबल वन, जियोपीएल, टाटा प्ले और एनएक्सटी डिजिटल केबल टीवी सहित कई प्रमुख प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही, देश ही नहीं बल्कि अस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले दर्शक भी इस नए चैनल का आनंद ले सकेंगे। पठानकोट से शुरू हुई यह नई उड़ान पंजाब की आवाज को देश-दुनिया तक पहुंचाने का एक दृढ़ संकल्प है, जिसके तहत 'चुनावी सवाल आपके और पड़ताल हमारी' का यह सफर लगातार जारी रहेगा।

भाजपा प्रदेश सचिव राकेश शर्मा ने व्यापार मंडल पठानकोट के साथ की बैठक, शहर के विकास और व्यापारिक मुद्दों पर हुई चर्चा

एक्स्पूरेट मिरर

भाजपा पंजाब के प्रदेश सचिव श्री राकेश शर्मा ने व्यापार मंडल पठानकोट के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की विभिन्न समस्याओं और व्यापारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तारपूर्वक बातचीत की। इस दौरान टिंबर मार्केट की समस्याओं, पठानकोट एयरपोर्ट को दोबारा सुचारू रूप से चालू करवाने, पर्यटन को बढ़ावा देने और टूरिज्म इंडस्ट्री के विकास के लिए विशेष पैकेज जैसे अहम विषयों पर विचार किए गए। इसके साथ ही पठानकोट में व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर शहर के आर्थिक विकास को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर व्यापार मंडल पठानकोट के चेयरमैन श्री अनिल महाजन, फाउंडर श्री एस.एस. बाबा, पीआरओ श्री नारायण दीप सिंह और सचिव श्री राज्येवानंद जी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा पंजाब के प्रदेश सचिव श्री राकेश शर्मा ने व्यापार मंडल पठानकोट की सराहना करते हुए

कहा कि पठानकोट में राजनीतिक लोगों से बढ़कर तबाह हो रहे हैं। वहीं, व्यापार मंडल के फाउंडर व्यापार मंडल के पदाधिकारी जनता की सेवा और लोगों का विश्वास जीतने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल पठानकोट हमेशा से ही सच की लड़ाई लड़ता आया है और शहर के लोगों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाता रहा है। बैठक के दौरान व्यापार मंडल के सचिव राजीव आनंद ने टिंबर मार्केट और पठानकोट की पहचान का जिक्र करते हुए बताया कि एशिया का पहले नंबर का टिंबर मार्केट पठानकोट में था जो अब खत्म हो गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि पठानकोट में रंजीत सागर डैम बनने के बाद पैसा आना कम हुआ है, जबकि पठानकोट धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा टूरिज्म हब बन सकता है। इसके अलावा उन्होंने नशे के मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि नशे के सौदागरों पर नकेल कसने की सख्त जरूरत है क्योंकि इससे हमारे बच्चे और युवा



एस.एस. बाबा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पठानकोट के लोगों के साथ आखिर क्या हो रहा है और शहर के विकास को लेकर किए जा रहे वादों की हकीकत क्या है। उन्होंने कहा कि जब भी सरकारें आईं, उन्होंने नरशा मुक्त करने के दावे किए, लेकिन धरातल पर हालात इसके विपरीत नजर आते हैं। बैठक में अन्य सदस्यों ने भी शहर की बेहतीर, रोजगार के साधनों, कारोबारियों की समस्याओं और शहर के उज्ज्वल भविष्य को लेकर अपने विचार रखे

पठानकोट : मीरपुर कॉलोनी में कोर्ट के आदेश लागू करवाने की उठी मांग, वेलफेयर सोसाइटी ने स्पष्ट किया अपना रुख

एक्स्पूरेट मिरर

पठानकोट की मीरपुर कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने एक अहम बैठक कर अदालत के आदेशों की लागू करवाने को लेकर चल रहे विवाद पर अपना स्पष्ट पक्ष रखा है। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने दोटूक शब्दों में कहा कि वे किसी भी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विरोध में नहीं हैं, बल्कि उनकी एकमात्र मांग यह है कि सारा काम कानून के मुताबिक होना चाहिए और यदि कहीं भी अवैध निर्माण हुआ है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले नगर निगम की टीम अदालत के आदेशों को लागू करवाने के लिए मौके पर पहुंची थी, लेकिन वहां अदालत के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों के आदेशों का



पूरा सम्मान होना चाहिए तथा प्रशासन को बिना किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना चाहिए। इस संबंध में सोसाइटी के पदाधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर से इस मामले में दखल देने और कोर्ट के आदेशों को धरातल पर लागू करवाने की पुर्णजोर मांग की है। उन्होंने दोहराया कि

सोसाइटी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी मंशा सिर्फ यह है कि अवैध निर्माण पर नियमांसार कार्रवाई हो। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और अदालत के आदेशों को लागू करवाने के लिए आगे क्या प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।

बेटी की बहादुरी आई काम : बदमाशों की झपटमारी नाकाम, दो गिरफ्तार, एक फरार



एक्स्पूरेट मिरर

पठानकोट जिले के आनंदपुर रड़ा पर एक महिला की सोने की बालियां झपटकर भाग रहे 3 बदमाशों में से 2 को उसकी बेटी ने स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया, जबकि उनका तीसरा साथी फरार हो गया। घटना खिवाह शाम की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पीपल मोहल्ला निवासी सुमन अपनी बेटी शिल्पा के साथ स्कूटी पर दांतों का चेकअप कराने आनंदपुर रोड स्थित क्लीनिक जा रही थीं। रास्ते में उन्हें अपनी बुआ को करवाचौथ के व्रत का सामान भी देना था। आनंदपुर रड़ा पहुंचकर जैसे ही सुमन स्कूटी से उतरतीं तो 3 बदमाशों ने उनकी सोने की बालियां झपट लीं। इससे सुमन सड़क पर गिर गईं और घायल हो गईं। जिले में झपटमारी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पिछले दो महीने

में करीब 10 वारदातें हो चुकी हैं। वारदात के बाद शिल्पा ने हिम्मत दिखाते हुए भाग रहे झपटमारों का पीछा किया। उसने शोर मचाया और लोगों की मदद से दो युवकों को दबोच लिया, जबकि तीसरा आरोपी फरार हो गया। पकड़े गए युवकों की तलाशी के दौरान दोनों बालियां बरामद कर ली गईं। एक बाली तुरंत मिल गई थी, जबकि दूसरी आरोपी ने अपने अंडरगार्मेट्स में छिपा रखी थी। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर थाना डिब्बोजन नंबर-1 की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गईं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। महिला के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, फरार चल रहे तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

पठानकोट के सैली रोड पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध निर्माण

तीन प्लॉट्स को मिलाकर खड़ा किया जा रहा विशाल ढांचा

इंफ्रामेंट ट्रस्ट की वीन बेल्ट पर भी कब्जा, अधिकारियों की खामोशी पर उठे गंभीर सवाल

एक्स्पूरेट मिरर

पठानकोट के सैली रोड स्थित गोल्डन एवेन्यू इलाके में इंफ्रामेंट ट्रस्ट के नियमों और टाउन प्लानिंग की संरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह पूरा इलाका इंफ्रामेंट ट्रस्ट के सीधे अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बेखोफ तरीके से गैर-कानूनी निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। कागजी दस्तावेजों और सरकारी नियमों के मुताबिक यह पूरा क्षेत्र रेजिडेंशियल ज़ोन घोषित है, जहाँ 8-8 मरले के अलग-अलग आवासीय प्लॉट्स आवंटित किए गए हैं। इसके विपरीत जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ तीन अलग-अलग प्लॉट्स की सीमाओं को पूरी तरह समाप्त कर उन्हें आपस में मिला दिया गया है और एक बहुत बड़ा अवैध ढांचा खड़ा किया जा रहा है।

टाउन प्लानिंग और नगर सुधार न्यास के कड़े नियमों के अनुसार तीन अलग-अलग आवासीय प्लॉट्स को एक साथ जोड़कर इस तरह के विशाल निर्माण का नक्शा



पास होना प्रशासनिक और कानूनी रूप से कतई संभव नहीं है। जब नियमों के तहत इस प्रकार के ढांचे का नक्शा स्वीकृत ही नहीं हो सकता, तो फिर दिन-दिहाड़े इतनी तेजी से यह अवैध निर्माण होना सीधे तौर पर व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा है। इसके साथ ही सबसे अधिक हैरान करने वाला पहलू यह है कि इस निर्माण के दौरान एनवायरमेंट पार्क के बिल्कुल सामने जनता के लिए छोड़ी गई आधिकारिक 'ग्रीन बेल्ट' को पूरी तरह से सर्वकार कर दिया गया है। सार्वजनिक उपयोग और

पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित इस हरी-भरी पट्टी पर बाकायदा अवैध कब्जा जमाकर उसे निर्माणाधीन परिसर के भीतर मिला लिया गया है और निजी स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण ने स्थानीय प्रशासन और इंफ्रामेंट ट्रस्ट की कार्यशैली पर गहरे संशय के बादल खड़े कर दिए हैं। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे नियम विरुद्ध निर्माण और संज्ञान लेते हुए इसे रोका जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

अधिकारी इस पूरी धांधली से बेखबर हैं या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे हैं। जाहिर तौर पर कानून और टाउन प्लानिंग के मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा यह अवैध कार्य बिना प्रशासनिक मिलीभगत और शह के संभव नजर नहीं आता। क्षेत्र के लोगों ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस अवैध कब्जे और गैर-कानूनी निर्माण पर तत्काल कड़ा संज्ञान लेते हुए इसे रोका जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में धूमधाम से मनाई गई 'आरंभ-2026' फ्रेशर पार्टी

चेयरमैन एसके पुंज ने विद्यार्थियों को दी सफलता की प्रेरणा

एक्स्पूरेट मिरर

श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बधानी कॉलेज में नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए 'आरंभ-2026' फ्रेशर पार्टी का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में ग्रुप के चेयरमैन एसके पुंज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि एमडी तुषार पुंज और रिया पुंज ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पारंपरिक स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद कॉलेज परिसर का माहौल पूरी तरह से उत्सवमय हो गया। कार्यक्रम के दौरान सीनियर और जूनियर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक मंच पर एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में चेयरमैन एसके पुंज ने कहा कि कॉलेज का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं,



बल्कि उन्हें एक कुशल और सफल प्रोफेशनल बनाना है। उन्होंने इस बात पर विशेष गर्व व्यक्त किया कि हाल ही में कॉलेज के चार विद्यार्थियों ने एमटेक की परीक्षा में पीटीयू (IKG PTU) की टॉप 10 रैंक में अपनी जगह बनाई है, जो संस्थान की उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता और विद्यार्थियों की मेहनत का प्रमाण है। वहीं सीएमडी तुषार पुंज ने नए विद्यार्थियों का खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें

जीवन में अनुशासन, लगन और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस यादगार अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. विपिन गुप्ता, डॉ. दिनेश महाजन, वॉइस प्रिंसिपल संजय पंडित, डॉ. संदीप शर्मा सहित समस्त शिक्षकगण, गैर-शिक्षण स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नए सत्र के साथ अमन भल्ला में लौटी रौनक, 'आरंभ-2026' ओरिएंटेशन से हुआ नवप्रवेशी छात्रों का भव्य स्वागत



एक्स्पूरेट मिरर

पठानकोट: अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 का शानदार आगान 'आरंभ-2026' ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ हुआ। नए सत्र की शुरुआत होते ही कॉलेज परिसर में नवप्रवेशी छात्रों की चहलकदमी और ऊर्जा से एक बार फिर रौनक लौट आई। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ संस्थान के प्रेजिडेंट रमन भल्ला, चेयरपर्सन अनु भल्ला, विशेष रूप से पहुंचे ट्रस्टी आकाश नारांग और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. पुजा ओहरी ने मां सरस्वती के समक्ष

दीप प्रज्वलित कर और सरस्वती वंदना के साथ किया। इस दौरान संस्थान के प्रबंधन ने नए विद्यार्थियों को अनुशासन का महत्व समझाते हुए कॉलेज के शैक्षणिक कीर्तिमानों और यहां से उत्तीर्ण हुए पूर्व छात्रों की शानदार उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पहले दिन कॉलेज प्रबंधन और विभिन्न विभागों की ओर से नए छात्रों के स्वागत के लिए परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था। ओरिएंटेशन के दौरान विद्यार्थियों को कैम्पस की शैक्षणिक प्रणाली, कोर्स संरचना, परीक्षा पद्धति, पुस्तकालय,



क्लब्स, सोसाइटियां, खेलकूद तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से अवगत कराया गया। वहीं सीनियर छात्रों ने भी फ्रेशर्स का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें कैम्पस की परंपराओं, गतिविधियों और अनुशासन से परिचित कराया। सुबह से ही कॉलेज परिसर में उमंग का माहौल देखने को मिला, जहां नए छात्रों में अपने भविष्य को लेकर एक विशेष आशा और उत्साह नजर आया। कॉलेज मैनेजमेंट ने नए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के साथ-साथ अपने

व्यक्तित्व को निखारना बेहद जरूरी है और इसके लिए अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्थान की ओर से छात्रों को एक सुरक्षित, अनुशासित और प्रेरणादायक माहौल देने का पूरा भरसा दिया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल गौरव सैनी, डॉ. नीरज पूनी, डॉ. रजत अरोड़ा, डॉ. जगदीश सिंह, प्रिंसिपल डॉ. नूतन गुप्ता, डीन मैनेजमेंट तरुण ओहरी, एचओडी विक्रम सुर्मिया, डीन एक्स्ट्रा एक्टिविटी सुनेन व आस्था समेत सगहू स्टाफ सदस्य और शिक्षक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

हिन्दू कोऑपरेटिव बैंक पठानकोट ने पूरे किए 100 साल, शताब्दी समारोह में शेरधरकों को बांटी जाएगी 1.30 करोड़ रुपये की राशि

एक्स्पूरेट मिरर

पठानकोट में हिंदू कोऑपरेटिव बैंक ने अपने 100 साल पूरे होने पर भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन किया। इस विशेष अवसर पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारुचक ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके अतिरिक्त पूर्व मंत्री मास्टर मोहन लाल, सुजानपुर के विधायक नरेश पुरी और शहर के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर मौजूद रहे। समारोह के दौरान बैंक के 100 वर्ष के ऐतिहासिक सफर को याद किया गया और इसके साथ ही बैंक की ओर से शेरधरकों के लिए एक अहम घोषणा की गई। बैंक के करीब 13,000 हिस्सेधारकों को कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपये की



राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि करीब 13 साल बाद बैंक से जुड़े इन लोगों को यह राशि मिलने जा रही है और बैंक की ओर से यह भुगतान शत-प्रतिशत दर से किया जा रहा है। बैंक के चेयरमैन सतीश महिंद्रा और वाइस चेयरमैन विनोद महाजन ने जानकारी दी कि पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान बैंक ने लगभग 26 करोड़ रुपये की बिक्री की है, जिससे बैंक की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने

में बड़ी मदद मिली है। इस दौरान बैंक की वार्षिक आम सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के कामकाज और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा हुई। वर्ष 1926 में स्थापित हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के शताब्दी वर्ष के इस ऐतिहासिक पल पर बैंक के पदाधिकारियों, हिस्सेदारों और शहर की प्रमुख हस्तियों ने मिलकर इस बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाया।

सुजानपुर में मावां-धीयां सत्कार योजना को लेकर आप की विशेष बैठक

हलका इंचार्ज स्वरन सिंह सलारिया रहे मौजूद



एक्स्पूरेट मिरर

पठानकोट के सुजानपुर में आम आदमी पार्टी की ओर से 'मावां-धीयां सत्कार योजना' के तहत महिलाओं के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सुजानपुर के हलका इंचार्ज स्वरन सिंह सलारिया विशेष रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान स्वरन सिंह सलारिया ने महिलाओं के साथ विस्तार से बातचीत की और योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते

हुए इसकी पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने महिलाओं को बताया कि जिस प्रकार उन्होंने पहले मेहनत की है, उसी तरह आगामी चुनावों के समय भी पार्टी के लिए काम करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की नीतियों, पिछले पांच वर्षों में किए गए विकास कार्यों तथा आगामी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के अन्य स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी भारी संख्या में मौजूद रहे।